PRGI. No.: MHMUL/25/A2419

प्यूपिल्स टाइम्स

PUPILS TIMES

Volume : 1 ‣ Issue : 23 ‣ Mumbai ‣ Friday, 10 July to 16 July 2026 ‣ Weekly ‣ Pages : 8 ‣ Price : 3 Rs.

इंडोनेशिया खरीदेगा भारत की ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें

जकार्ता। भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंगलवार (7 जुलाई) को दोनों देशों ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइल को लेकर अहम समझौता किया। इस डील से जहां भारत और इंडोनेशिया के रणनीतिक रिश्ते और मजबूत होंगे, वहीं भारत की घरेलू रक्षा उद्योग और रक्षा निर्यात को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। जानकारी के अनुसार, इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त बैटरियां खरीद सकता है। इसके अलावा, डीआरडीओ द्वारा विकसित 'अस्त्र' एयर-टू-एयर मिसाइल की खरीद पर भी सहमति बनी है। 'अस्त्र' एक अत्याधुनिक बियॉन्ड-विजुअल-रेंज (BVR) मिसाइल है, जिसे लंबी दूरी से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर सटीक निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। यह तेजी से दिशा बदलने वाले लक्ष्यों को भी प्रभावी ढंग से नष्ट करने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ता विश्वास रक्षा,

सुरक्षा और समुद्री सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा आदान-प्रदान, आपदा प्रबंधन और रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। उनका कहना था कि यह साझेदारी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता को भी मजबूती देगी। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। यह मिसाइल जमीन, समुद्र और कुछ मामलों में हवाई प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च की जा सकती है। इसकी तेज रफ्तार, लंबी मारक क्षमता और सटीक निशाने की वजह से दुनिया के कई देशों की इस पर नजर है। भारत पहले भी कई देशों को ब्रह्मोस निर्यात करने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा वर्ष 2023 के बाद इंडोनेशिया की पहली आधिकारिक यात्रा है। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। **(शेष पेज 5 पर)**

पीएम मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान

■ इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने के लिए इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान 'बिन्तांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया' प्रदान किया गया। **VC** अब तक कुल 35 सम्मान मिल चुके हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने यह पदक प्रधानमंत्री को दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान मिलने के बाद कहा कि मैं राष्ट्रपति, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान भारतीयों का है। इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है।

हिंद महासागर की सुरक्षा करेंगे दोनों देश

■ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंद प्रशांत पर दोनों देशों का रूख स्पष्ट है। भारत हमेशा से आसियान देशों को महत्व देता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के तट रक्षक बल हिंद महासागर की सुरक्षा को और मजबूत बनाएंगे। इससे पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र के महत्व को उजागर करते हुए कहा कि ये पूरी तरह स्वतंत्र और पारदर्शी है और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार है।

इंडोनेशिया के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार

■ भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और इंडोनेशिया के नेशनल एजेंसी ऑफ ड्रग एंड फूड केंट्रोल के बीच भी करार हुआ है। इसके तहत दोनों देश चिकित्सा उपकरणों के निर्माण पर काम करेंगे। इंडोनेशिया के बाजार में भारतीय मेडिकल उत्पादों की पहुंच बढ़ेगी। स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने पर भी दोनों देश सहमत हुए हैं। भारत इंडोनेशिया के डॉक्टरों और स्वास्थ्य क्षेत्र के लोगों को दक्ष बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

यूपी में शिक्षकों को बड़ी सौगात

पांच लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा शुरू

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों और शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य योजना की शुरूआत की। इस योजना से शिक्षक और उनके परिवार बिना किसी परेशानी के चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' की शुरूआत की। इसके तहत प्रदेश के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज सुविधा मिलेगी। इस योजना से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े करीब 15 लाख शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के साथ शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइये और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा अपना वादा पूरा किया है। अब शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप नई पीढ़ी को बेहतर शिक्षा दें। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यार्थियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 1,320 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की। उन्होंने बताया कि

प्रत्येक विद्यार्थी को स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, बैग और अन्य जरूरी सामान के लिए 1,200 रुपए दिए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना समाज की जिम्मेदारी है और इसमें शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ह्यनिपुण भारत अभियानह्ण का जिक्र करते हुए कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा, जब शिक्षा की नींव मजबूत होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार हुए हैं और शिक्षकों को समाज में सम्मानजनक स्थान मिल रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की सामाजिक सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

अगले वर्ष तक सभी राज्य मुख्यालयों पर शुरू होंगे FRRO कार्यालय, 62 एयरपोर्ट पर बढ़ेंगी यात्री सुविधाएं

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु ने प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था एवं आप्रवासन प्रणाली की समीक्षा की। सभी हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से स्वचालित एक्स-रे ट्रे रिटर्न प्रणाली लागू की जाएगी। अगले वर्ष तक सभी राज्य मुख्यालयों पर एफआरआरओ कार्यालय स्थापित होंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने अगरतला एवं जेवर हवाई अड्डों पर अधिकृत आप्रवासन जांच चौकियां शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के सुरक्षा मापदंड अनुसार यात्री-सुविधा बढ़ाने और वाणिज्यिक क्षेत्र को निर्धारित मानक में ही रखने के लिए 21 प्रक्रियाधीन तथा शेष 41 एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए पैसेंजर्स ट्रैफिक के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इन 62 एयरपोर्ट पर अगले दो वर्ष में कार्य पूर्ण किया जाए। नागरिक विमानन मंत्रालय पैसेंजर ट्रैफिक और एयर ट्रैफिक के आधार पर सभी एयरपोर्ट्स के लिए एरोब्रिज की संख्या संबंधी मानदंड निर्धारित करे। बैगेज ड्रॉप की सुविधा प्रमुख 16 हवाई अड्डों के अतिरिक्त अन्य उच्च पैसेंजर आवागमन वाले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी उपलब्ध कराई जाए।

टीएमसी के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ फ्रीज

कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से जुड़े संदिग्ध फंड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) के तहत अपनी जांच तेज कर दी है। केंद्रीय एजेंसी ने कोलकाता में टीएमसी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनमें लगभग 440 करोड़ रुपये जमा हैं।

यह पूरी कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा तीन मुख्य बैंक खातों पर लगाए गए 'डेबिट फ्रीज' के बाद हुई है। पुलिस ने बागी विधायकों के एक गुट की शिकायत के बाद इन खातों से होने वाले सभी लेन-देन और निकासी पर रोक लगा दी थी। इस गुट का नेतृत्व ऋतब्रत बनर्जी कर रहे हैं। अब ईडी ने इस मामले को अपने हाथ में लेकर जांच का दायरा बढ़ा दिया है।

अल नीनो की चुनौती पर सरकार अलर्ट

केंद्रीय मंत्री शिवराज ने बताया कृषि क्षेत्र के लिए क्या रणनीति बना

नई दिल्ली: अल नीनो के संभावित प्रभाव से उपजी मानसून की अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तैयारी, स्पष्ट रणनीति और मजबूत ग्राउंड एक्शन के साथ हालात को संभालने में जुटी है। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन उनसे निपटने के लिए सिस्टम पहले से सक्रिय और सतर्क है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि जून में 33 प्रतिशत कम बारिश के बाद जुलाई में स्थिति में सुधार आया है और अब यह कमी घटकर 24 प्रतिशत रह गई है।

हाल के दिनों में देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे कम वर्षा वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई में बारिश और रफ्तार पकड़ेगी, जिससे खरीफ बुवाई में तेजी आएगी।

संपादकीय

आस्था के मुखौटे में अवसरवादी राजनीति

राम मंदिर चढ़ावा अपहार प्रकरण ने हिंदू समाज के विश्वास को ठेस पहुंचाई है। धर्म शास्त्रों में मंदिर से जुड़ी संपत्ति के लिए 'देवद्रव्य' शब्द का प्रयोग मिलता है। इसमें केवल देवताओं के आभूषण ही नहीं, बल्कि भूमि, दान, अनाज, पशुधन और पूजा सामग्री जैसी सभी वस्तुएं शामिल थीं। एक बार समर्पित हो जाने के बाद यह संपत्ति व्यक्तिगत नहीं रह जाती थी, और इसके अपहार को प्रायः केवल आर्थिक अपराध के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इन्हें आस्था और सामाजिक विश्वास पर चोट के रूप में भी समझा जाता है। विपक्षी दल इस प्रकरण की आड़ में भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेपों की बौछार कर रहे हैं। कुछ वहीं दल और नेता हैं जिन्होंने अयोध्या केस, राम मंदिर निर्माण और मंदिर से जुड़े विशेष अवसरों पर बड़ी निर्लज्जता से निम्नस्तरीय राजनीति की। रामकाज में पग–पग पर बाधा डाली। ऐसे में इन दलों और नेताओं का एकाएक भगवान राम और राम मंदिर के प्रति उमड़ा प्रेम, आदरभाव, चिंता और सक्रियता उन्हें प्रश्नों और संदेह के घेरे में खड़ा करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि, तथाकथित सेक्युलर वादी और फर्जी नैरेटिव चलाने वालों की राजनीति तेजी से सिमट रही है। हिंदू मानस इनके फर्जी नैरेटिव और प्रोपेगेंडा में अब फंस नहीं रहा। ऐसे में अपनी बची खुची राजनीति बचाने के लिये ये हिंदू समाज को बांटने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। राम मंदिर चढ़ावा अपहार प्रकरण में विपक्ष को राजनीतिक ऑक्सीजन मिलती दिख रही है। इस प्रकरण में भाजपा की छवि धूमिल कर विपक्ष उसके जनाधार और वोट बैंक को प्रभावित करने के सपने देख रहा है। लेकिन इस राजनीति और पैंतरेबाजी के बीच विपक्ष यह भूल जाता है कि हिंदू मानस सुनता सबकी है; वो सबको अवसर भी देता है; सबको आजमाता भी है। लेकिन एक बार जांचने–परखने और समझने के बाद वो ऐतिहासिक निर्णय लेता है। इसका सबसे ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं। चढ़ावा अपहार प्रकरण से हिंदू मानस व्यथित है। उसके विश्वास को गहरी ठेस लगी है। लेकिन अपने आराध्य प्रभु श्रीराम के प्रति उसकी आस्था और श्रद्धा अटूट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आश्वस्त कर चुके हैं कि दोषी बचेंगे नहीं। जनमानस योगी जी के वचनों पर विश्वास करता है। विशेष जांच दल मामले की जांच कर रहा है। आठ आरोपी जेल में हैं। इस दुखद प्रकरण से सबक लेते हुए ऐसी फूलप्रूफ व्यवस्था होनी चाहिए कि भविष्य में गड़बड़ी की गुंजाइश ने रहे। वहीं हिंदू मानस के विश्वास जो ठेस लगी है, उसकी पुनर्प्रतिष्ठा भी जरूरी है।

आस्था की रक्षा केवल श्रद्धा से नहीं, जवाबदेही से भी होगी

अयोध्या के श्री रामलला मंदिर में दानपात्रों से धन चोरी की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह केवल एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, धार्मिक संस्थानों की विश्वसनीयता और उनके प्रशासनिक प्रबंधन से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। ऐसे समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का सार्वजनिक वक्तव्य विशेष महत्व रखता है। इस वक्तव्य का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आस्था के केंद्र भी जवाबदेही से ऊपर नहीं हो सकते। यदि किसी धार्मिक संस्थान में सुरक्षा या प्रशासनिक व्यवस्था में चूक होती है, तो उसे छिपाने के बजाय स्वीकार करना और सुधारना ही उसकी गरिमा को बढ़ाता है। यही स्वस्थ संस्थागत संस्कृति का आधार है। राम मंदिर केवल एक भव्य निर्माण नहीं, बल्कि भारतीय समाज की सांस्कृतिक चेतना, विश्वास और लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का प्रतीक है। ऐसे संस्थान की प्रतिष्ठा उसकी ऊँची दीवारों या भव्य शिखरों से नहीं, बल्कि उसके प्रबंधन की पारदर्शिता और नैतिकता से भी तय होती है। श्रद्धालु जब दानपात्र में धन डालता है, तो वह केवल रुपये नहीं देता, बल्कि अपना विश्वास भी सौंपता है। उस विश्वास की रक्षा करना प्रत्येक संबंधित संस्था और प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। दत्तात्रेय होसबाले का वक्तव्य इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि उसमें घटना को हल्के में लेने का कोई संकेत नहीं दिखता। यह स्पष्ट संदेश है कि दोषियों की पहचान हो, निष्पक्ष जांच हो और कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई हो। इससे यह भी संकेत मिलता है कि धार्मिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए पारदर्शिता आवश्यक है, न कि मौन। इस घटना को राजनीतिक चश्मे से देखने की जल्दबाजी भी उचित नहीं होगी। किसी भी सार्वजनिक वक्तव्य की व्याख्या उसके शब्दों और आशय के आधार पर होनी चाहिए, न कि पूर्वाग्रहों के आधार पर। यदि वक्तव्य का केंद्र बिंदु आस्था की रक्षा, जवाबदेही और निष्पक्ष जांच है, तो उसी संदर्भ में उसका मूल्यांकन होना चाहिए। यह घटना एक बड़े राष्ट्रीय विमर्श का अवसर भी देती है। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर प्रतिदिन करोड़ों रुपये का दान आता है। क्या सभी संस्थानों में आधुनिक सुरक्षा प्रणाली, डिजिटल निगरानी, नियमित लेखा–परीक्षा और स्वतंत्र ऑडिट जैसी व्यवस्थाएँ पर्याप्त रूप से लागू हैं? यदि नहीं, तो अब इस दिशा में गंभीर और समयबद्ध पहल होनी चाहिए। धार्मिक संस्थाओं की पवित्रता केवल पूजा–पद्धति से नहीं, बल्कि उनके प्रशासनिक चरित्र से भी तय होती है। पारदर्शी व्यवस्था आस्था को मजबूत करती है, जबकि लापरवाही या अपारदर्शिता संदेह को जन्म देती है। इसलिए यह समय दोषारोपण का नहीं, बल्कि व्यवस्था को अधिक विश्वसनीय बनाने का है। रामलला मंदिर दान चोरी प्रकरण अंततः हमें यही सिखाता है कि आस्था और उत्तरदायित्व एक–दूसरे के पूरक हैं। जहाँ श्रद्धा है, वहाँ ईमानदारी और पारदर्शिता भी उतनी ही अनिवार्य होनी चाहिए। यदि इस घटना से सबक लेकर व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाता है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी भविष्य के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन का आधार बन सकती है।

धार्मिक संस्थाओं की पवित्रता केवल पूजा–पद्धति से नहीं, बल्कि उनके प्रशासनिक चरित्र से भी तय होती है। पारदर्शी व्यवस्था आस्था को मजबूत करती है, जबकि लापरवाही या अपारदर्शिता संदेह को जन्म देती है। इसलिए यह समय दोषारोपण का नहीं, बल्कि व्यवस्था को अधिक विश्वसनीय बनाने का है।

पर्यावरण नहीं, अस्तित्व का प्रश्न है वनों का संरक्षण

भारतीय संस्कृति में प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है। हमारे पर्व और उत्सव केवल सामाजिक उल्लास के अवसर नहीं रहे बल्कि प्रकृति और मानव के सह–अस्तित्व के प्रतीक भी रहे हैं। भारतीय परंपरा में वनों को देवतुल्य माना गया है। वे केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि पृथ्वी के फेफड़े, जैव विविधता के सबसे बड़े आश्रय, नदियों के संरक्षक, जलवायु संतुलन के प्रहरी तथा करोड़ों लोगों की आजीविका के आधार हैं। वनों की स्थिति विश्व स्तर पर चिंताजनक बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, पृथ्वी का केवल लगभग 31 प्रतिशत भूभाग ही वनाच्छादित है जबकि प्रतिवर्ष लाखों हेक्टेयर वन क्षेत्र अवैध कटाई, औद्योगिकीकरण, खनन और अवसंरचनात्मक विकास की भेंट चढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो आगामी दशकों में विश्व के अनेक वर्षावन गंभीर संकट में पड़ सकते हैं। ऐसे समय में भारत जैसे विशाल और जैव विविधता से समृद्ध देश की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। भारत ने हाल के वर्षों में वन संरक्षण और वृक्षारोपण की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण की भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) के अनुसार, देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण बढ़कर 8,27,357 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17 प्रतिशत है। इसमें 7,15,343 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र तथा 1,12,014 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आवरण शामिल है। पिछले आकलन की तुलना में कुल हरित आवरण में 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है जबकि अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ उसके बाद आते हैं। वहीं वन घनत्व के अनुपात में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय अग्रणी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट में भारत को कुल वन क्षेत्र के आधार पर विश्व में नौवां स्थान तथा वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में अग्रणी देशों में स्थान प्राप्त हुआ है। आज वन मानव स्वास्थ्य के सबसे बड़े संरक्षक बन चुके हैं। वायु प्रदूषण, जल संकट और भूमि के मरुस्थलीकरण जैसी समस्याओं का सबसे प्रभावी और किफायती समाधान वृक्ष ही हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन की गति को धीमा करते हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, वर्षा चक्र को संतुलित रखते हैं, भूजल स्तर बनाए रखते हैं तथा मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण कैंसर, हृदय रोग, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों में तेजी से वृद्धि हो रही है। साथ ही, अनियमित मानसून, भीषण हीटवेव, सूखा, क्लाउडबर्स्ट और जंगलों में आग जैसी घटनाएं स्पष्ट संकेत हैं कि प्रकृति का संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। इस संकट से निपटने के लिए भारत ने वर्ष 2030 तक अतिरिक्त 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन सिंक विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें वनों की भूमिका निर्णायक होगी। जब तक वृक्षारोपण को जनभागीदारी और जन–जिम्मेदारी का अभियान नहीं बनाया जाएगा, तब तक हरित भारत का सपना अधूरा रहेगा। विकास और पर्यावरण परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक–दूसरे के पूरक हैं। आर्थिक प्रगति, आधुनिक तकनीक और अवसंरचनात्मक विकास आवश्यक हैं किंतु वे स्वच्छ वायु, शुद्ध जल और संतुलित जलवायु का विकल्प नहीं बन सकते। यदि वन सुरक्षित रहेंगे तो नदियां जीवित रहेंगी, भूजल समृद्ध होगा, जैव विविधता संरक्षित रहेगी और मानव सभ्यता का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।

प्यूपिल्स टाइम्स

महाराष्ट्र में बारिश से मचा हाहाकार

मुंबईः महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और भूस्खलन, जलभराव व परिवहन में रुकावट जैसी समस्याएं पैदा हो गई हैं। इसे देखते हुए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) ने राज्य के कई हिस्सों में बचाव और राहत कार्य तेज कर दिए हैं। इस बीच भारतीय नौसेना ने कहा है कि लगातार हो रही भारी बारिश के कारण वेस्टर्न नेवल कमांड को हाई अलर्ट पर रखा गया है और राज्य प्रशासन द्वारा अनुरोध किए जाने पर मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने मौसम की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए नागरिकों से मॉनसून टूरिज्म और गैर-जरूरी काम से बाहर जाने से बचने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि आधिकारिक सलाह को नजरअंदाज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

उन्होंने कहा, "राज्य में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। सड़कें और रेलवे रूट बंद कर दिए गए हैं और पुणे-मुंबई ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी बंद है। स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। मुंबई में मंत्रालय में आपदा प्रबंधन की बैठक बुलाई गई है। मैं नागरिकों को सलाह देता हूं कि वे मुंबई में टूरिज्म या घूमने-फिरने के लिए बाहर न निकलें। हम जल्द ही आगे के फैसलों की घोषणा करेंगे।"

करोड़ों खर्च, फिर भी हर मानसून में क्यों डूब जाती है मुंबई?

■ बारिश का मौसम आते ही मुंबई में हर साल जलभराव, ट्रैफिक जाम, लोकल ट्रेन सेवाओं में बाधा और आम लोगों की परेशानी की तस्वीर सामने आ जाती है। करोड़ों रुपये के बजट, नालों की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम की मरम्मत और प्रशासनिक तैयारियों के बावजूद कुछ घंटों की तेज बारिश शहर की रफ्तार थाम देती है। इस बार भी सायन, कुर्ला, दादर, हिंदमाता और मिलन सबवे जैसे इलाकों में पानी भर गया, कई अंडरपास डूब गए और मुंबई-पुणे मार्ग भी प्रभावित हुआ। विशेषज्ञों के मुताबिक मुंबई में बार-बार बाढ़ की मुख्य वजह शहर की भौगोलिक स्थिति, हाई टाइड, तेजी से हुआ शहरीकरण, ड्रेनेज सिस्टम पर बढ़ता दबाव, मीठी नदी पर अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन है। जब तक दीर्घकालिक शहरी योजना, मजबूत जल निकासी व्यवस्था, नदी संरक्षण और बेहतर कचरा प्रबंधन पर प्रभावी काम नहीं होगा, तब तक हर मानसून में मुंबई के डूबने की तस्वीरें दोहराती रहेंगी।

नासिक के त्रयंबकेश्वर मंदिर में आई बाढ़ तो मुंबई बनी हुई है समंदर

▶▶ महाराष्ट्र में बारिश से तबाही! ▶▶ त्र्यंबकेश्वर मंदिर के कपाट बंद

महाराष्ट्र में पिछले कई घंटों से रुक-रुक कर हो रही बारिश हो रही है। एक तरफ जहां लोगों को भारी जलभराव का सामना करना पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर नदियों और बांधों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में जहां मुंबई पानी-पानी हो गई है तो नासिक में विश्व प्रसिद्ध त्रयंबकेश्वर मंदिर में भी बारिश का पानी घुस आया है। वहीं, त्र्यंबकेश्वर मंदिर को भी बंद कर दिया गया है। नासिक जिले की पांच तहसीलों में भारतीय मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। त्र्यंबकेश्वर और इगतपुरी क्षेत्र में रात से ही मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने त्र्यंबकेश्वर-नासिक क्षेत्र में बादल फटने जैसी अत्यधिक बारिश और करीब 300 मिलीमीटर तक वर्षा की संभावना जताई है। भारी बारिश और रेड अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया है। बारिश और खराब मौसम को देखते हुए 12 ज्योतिलिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर और नासिक का सप्तश्रृंगी माता मंदिर भी बंद रखा गया है। प्रशासन ने दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि त्र्यंबकेश्वर आने वाले वाहनों को नासिक और इगतपुरी में ही रोककर वापस भेजा गया।

पुणे : पल भर में ढहा 2 मंजिला घर, बाल-बाल बचे लोग

महाराष्ट्र के पुणे शहर के पेठ स्थित धनगर गली में सोमवार को एक पुराना दो मंजिला घर अचानक भरभराकर ढह गया. घटना के समय इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग दहशत में आ गए। हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि या घायल होने की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार, इमारत काफी पुरानी थी और उसके जर्जर होने की आशंका पहले से जताई जा रही थी। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लेकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। विभाग की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के चलते किसी बड़े हादसे को टाल दिया गया। फिलहाल प्रशासन ने आसपास के क्षेत्र की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इमारत किन कारणों से ढही। साथ ही आसपास की अन्य जर्जर इमारतों का भी निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

मानखुर्द इलाके में एक तीन मंजिला इमारत ढहने से छह लोगों की मौत

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के मानखुर्द इलाके में हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। जनता नगर की पांचवीं गली में स्थित ग्राउंड प्लस टू (तीन मंजिला) आरसीसी इमारत अचानक ढह गई और उसके बगल में बने एक टीन के घर पर जा गिरी। इस हादसे में एक महिला और पांच बच्चों समेत 6 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, जिस इमारत का हिस्सा गिरा, उसमें सुबह से ही टाइल्स और प्लास्टर टूटकर गिर रहे थे। स्थानीय लोगों और किरायेदारों को अंदेशा हो गया था कि इमारत कभी भी ढह सकती है. खतरे को देखते हुए इमारत में रहने वाले सभी किरायेदारों ने समय रहते मकान खाली कर दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

इमारत के बिल्कुल पास बने टीन के मकान में रहने वाली एक महिला सुबह अपने चार बच्चों के साथ एहतियातन घर से बाहर निकल गई थी। शाम के समय बच्चों को भूख लगने पर वह खाना बनाने के लिए दोबारा अपने घर लौट आई। इसी दौरान पड़ोस की एक बच्ची खेलते-खेलते उनके घर पहुंच गई। महिला बच्चों के लिए खाना बना ही रही थी कि अचानक पास की तीन मंजिला इमारत भरभराकर उनके घर पर गिर गई। देखते ही देखते पूरा टीन का मकान मलबे में तब्दील हो गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस, दमकल विभाग और बचाव दल को सूचना दी। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे से सभी को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक महिला और पांचों बच्चों की मौत हो चुकी थी।

840 लीटर मिलावटी दूध जब्त, स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा

प्यूपिल्स टाईम्स संवाददाता

मुंबईः गुहेरी के आरे रोड स्थित एक डेयरी पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री पॉलिस कांबले और पुलिस उप-निरीक्षक श्री देवेन गांधी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ संयुक्त छापेमारी में 840 लीटर मिलावटी दूध जब्त किया गया। आरोपी डिटर्जेंट और रसायन मिलाकर दूध की मात्रा बढ़ा रहे थे। जब्त सामान की कीमत लगभग ₹90,000 है।

इस संबंध में FSSAI अधिनियम 2006 और BNS की धारा 274, 275, 336 (3) के तहत मामला दर्ज किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती. पूनम पाडुर्णे ने कहा कि इस प्रकार का दूध गुर्दे और यकृत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल FSSAI प्रमाणित स्रोतों से ही दूध खरीदें।

लोनावला-कर्जत घाट में भूस्खलन, लंबी दूरी की ट्रेनें रद्द और डायवर्ट

लोनावला-कर्जत घाट क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से मध्य रेलवे की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। इसका सीधा असर नासिक रोड रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनों पर पड़ा है। इस भूस्खलन के कारण कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, कुछ के मार्ग बदल दिए गए हैं, जबकि कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। मध्य रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, गाड़ी संख्या 11011 सीएसएमटी-धुलियया एक्सप्रेस, 11012 धुलिया-सीएसएमटी एक्सप्रेस और 12115 सीएसएमटी-सोलापुर एक्सप्रेस को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। लोनावला-कर्जत घाट क्षेत्र में भूस्खलन के बाद मध्य रेलवे ने कई लंबी दूरी की ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया है। रेलवे के अनुसार पुणे-भुज एक्सप्रेस, पुणे-अहमदाबाद एक्सप्रेस, अहमदाबाद-चेन्नई एक्सप्रेस, बेंगलुरु-जोधपुर एक्सप्रेस, चेन्नई-सीएसएमटी एक्सप्रेस, कोणार्क एक्सप्रेस और नांदेड़-पनवेल एक्सप्रेस सहित कई गाड़ियां अब अपने निर्धारित मार्ग के बजाय वैकल्पिक रूट से चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों का संचालन फिलहाल इगतपुरी-मनमाड-दौंड या सूरत-जलगांव-मनमाड मार्ग के जरिए किया जा रहा है।

ठाणे जिले में आफत की बारिश

ठाणे जिले में जून की औसत बारिश का 71 प्रतिशत हिस्सा हो चुका है। इसमें सबसे ज्यादा बारिश ठाणे शहर में और सबसे कम बारिश शहापुर तालुका में रिकॉर्ड की गई है। जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई की शुरूआत में भी अच्छी बारिश हो रही है। इस वजह से कई जगहों पर पानी भरने की घटनाएं सामने आई हैं।

बोरीवली होम लोन सेंटर में एसबीआई का 71वां स्थापना दिवस मनाया गया

मुंबईः बोरीवली स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन सेंटर में बैंक का 71वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। मुख्य अतिथि बोरीवली पश्चिम की नगर सेविका एवं बैंक की ग्राहक श्रीमती जिग्ना शाह ने एसबीआई के राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा में योगदान की सराहना की। इस अवसर पर कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को शिक्षा, खेलकूद और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया।

असिस्टेंट जनरल मैनेजर अश्विनी कुमार शर्मा ने बैंक की 71 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और उत्कृष्ट सेवा पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में वैद्य मैडम ने आभार व्यक्त किया। समारोह के सफल आयोजन में गणेश मकुते, मनोज गुप्ता सहित पूरी टीम का विशेष योगदान रहा।

प्यूपिल्स टाइम्स

कर्ज वसूली के नाम पर मनमानी पर लगेगी रोक

महाराष्ट्र में अवैध साहूकारी पर सख्त हुआ कानून, क्या प्रावधान बदले?

मुंबईः महाराष्ट्र विधानसभा ने गैरकानूनी तरीके से कर्ज देने वाले साहूकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई वाला विधेयक पारित कर दिया। इसमें बिना अनुमति के कर्ज देने वालों को अधिकतम सात साल की जेल और एक लाख रुपये तक जुमार्ने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक का मकसद कर्ज लेने वाले लोगों को सुरक्षा देना है। महाराष्ट्र साहूकारी (नियमन) (संशोधन) विधेयक, 2026 को सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने विधानसभा में पेश किया था। इसमें मौजूदा कानून में बदलाव कर बिना वैध लाइसेंस के कर्ज देने, फर्जी नाम से लाइसेंस लेने, बिना अनुमति वाली जगह से काम करने और कर्ज वसूली के लिए कर्ज लेने वालों को परेशान करने वालों पर सजा बढ़ाने का प्रस्ताव है।

बिना लाइसेंस कर्ज देने वालों पर क्या कार्रवाई होगी?

- बिना लाइसेंस के साहूकारी करने पर अधिकतम सजा पांच साल से बढ़ाकर सात साल की जाएगी।
- जुमार्ने की अधिकतम राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी जाएगी।
- विधेयक में फर्जी नाम से लाइसेंस लेने या बिना अनुमति वाली जगह से साहूकारी करने पर भी सजा बढ़ाने का प्रस्ताव है।
- पहली बार अपराध करने पर अधिकतम जेल की सजा एक साल साल से बढ़ाकर 3 साल और जुमार्ना 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया जाएगा।
- दोबारा अपराध करने पर अधिकतम जेल की सजा 5 साल से बढ़ाकर 7 साल और जुमार्ना 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाएगा।

कर्ज वसूली में परेशान करने पर क्या सजा होगी?

- इसके अलावा, कर्ज वसूली के दौरान कर्ज लेने वाले व्यक्ति से छेड़छाड़ करने या इसके लिए उकसाने पर भी सजा बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसमें जेल की सजा 2 साल से बढ़ाकर 3 साल और अधिकतम जुमार्ना 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाएगा। विधेयक के उद्देश्य और कारणों के अनुसार, मौजूदा सजा के प्रावधानों के बावजूद कुछ लोग और संस्थाएं अब भी अवैध रूप से कर्ज देने का काम कर रही हैं। इससे कर्ज लेने वाले लोगों को नुकसान हो रहा है और कानून का डर कम हो रहा है। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद बार-बार होने वाले अपराधों को रोकना, कर्ज लेने वालों को शोषण से बचाना और दोषियों की जवाबदेही तय करना है।

महाराष्ट्र में 1 अगस्त से बदल जाएंगे बाइक और टैक्सी के लिए नियम

परमिट के लिए मराठी आना जरूरी

मुंबईः महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एक अगस्त से बाइक और टैक्सी के लिए नियम बदल दिए हैं। ड्राइवर्स के लिए मराठी भाषा को भी अनिवार्य किया गया है। वर्तमान में महाराष्ट्र में करीब 4 से 4.5 लाख अवैध बाइक टैक्सियां संचालित हो रही हैं। इन्हें रेगुलेट करने के लिए राज्य सरकार 1 अगस्त से नई बाइक टैक्सी पॉलिसी लागू करने जा रही है। सरकार का तर्क है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और अब तक अवैध संचालन की वजह से हो रहे राजस्व नुकसान में भी कमी आएगी। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि केवल महाराष्ट्र के डोमिसाइल रखने वाले और मराठी समझने वाले लोगों को ही बाइक टैक्सी का परमिट दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेटरों को प्रतिदिन सरकार को 5 रुपये का शुल्क देना होगा। इसके अलावा, कुल आय का 2 फीसदी वेलफेयर फंड में जमा किया जाएगा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिवसेना विधायक दिलीप लांडे ने कहा कि अवैध बाइक टैक्सी ऑपरेटरों की वजह से ऑटो और टैक्सी चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं, इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सुनील प्रभु ने चिंता जताई कि कई ओला और उबर चालक शराब के नशे में वाहन चलाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई जोमैटो और स्विगी के डिलीवरी पार्टनर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। इस पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि वह परिवहन विभाग को विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश देंगे, ताकि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

बिजली का तार गिरने से दो लड़कियों की करंट लगने से मौत

■ गौरव सिंह/नवी मुंबई

नवी मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बीच एक बड़ा हादसा सामने आया। यहां जलभराव वाले हिस्से में करंट उतरने से टू-व्हीलर सवार दो छात्राएं बिजली की चपेट में आ गईं। करंट का तेज झटका लगते ही दोनों छात्राएं सड़क पर गिर पड़ीं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। राहत की बात यह है कि दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही थी। जानकारी के मुताबिक, यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों छात्राएं बाइक से नेरुल के एलपी ब्रिज के नीचे से गुजर रही थीं। लगातार बारिश के कारण वहां पानी जमा था। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पानी में करंट फैल गया, जिसकी चपेट में आने से दोनों युवतियां हादसे का शिकार हो गईं।

घटना की सूचना मिलते ही नवी मुंबई की मेयर सुजाता पाटिल मौके पर पहुंचीं और पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए बिजली विभाग और संबंधित अधिकारियों से तत्काल रिपोर्ट मांगी। मेयर सुजाता पाटिल ने कहा कि बारिश के दौरान खुले बिजली के तार, क्षतिग्रस्त केबल या अन्य विद्युत उपकरण लोगों की जान के लिए खतरा बन सकते हैं। उन्होंने नगर निगम के विद्युत अभियंताओं को निर्देश दिए कि जहां भी खुले तार या बिजली से जुड़ी खामियां हैं, उन्हें तत्काल ठीक किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विभिन्न विभाग अक्सर सड़कों की खुदाई तो कर देते हैं, लेकिन समय पर मरम्मत नहीं करते। इसी लापरवाही के कारण इस तरह की खतरनाक स्थिति पैदा हुई है। मेयर ने बिजली विभाग की जवाबदेही तय करने की भी बात कही।

सरकार ने व्यायामशालाओं के लिए सब्सिडी बढ़ाई

▶▶ पहले सरकार की ओर से 7 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा रही थी, अब आपको 14 लाख रुपये मिलेंगे

मुंबईः गुणवत्तापूर्ण और उत्कृष्ट एथलीट तैयार करने के लिए राज्य सरकार की खेल नीति लागू की गई है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यायामशालाएँ बनाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। अब जिम के लिए सब्सिडी दोगुनी कर दी गई है। पहले 7 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाती थी। अब रुपये की सब्सिडी 14 लाख दिए जाएंगे। राज्य में 2012 में खेल नीति लागू की गयी थी। पहले व्यायामशाला के लिए दो लाख रुपये का अनुदान दिया जाता था। सरकार से शिकायतें और अनुरोध प्राप्त हुए थे कि यह सब्सिडी उपलब्ध नहीं है। फिर 2019 में सरकार ने सब्सिडी राशि बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी। उसके बाद भी विभिन्न सामग्रियों की बढ़ती मांग एवं कीमत में वृद्धि के कारण अनुदान कम होता जा रहा था। लगातार सब्सिडी बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने सब्सिडी की राशि 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 14 लाख रुपये कर दी। इस संबंध में 23 अप्रैल 2025 को आदेश जारी किया गया था।

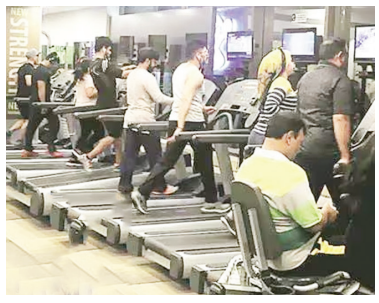

कहां और कैसे करें आवेदन? : व्यायामशाला स्थापित करने के लिए जिला खेल अधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। आवेदन सीधे जिला खेल अधिकारी कार्यालय में या यदि संभव न हो तो तालुका खेल अधिकारी कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

मापदंड क्या है? : व्यायामशाला के निर्माण के लिए पर्याप्त एवं आवश्यक मात्रा में स्थान होना चाहिए। बजट बनाकर जमा करना होगा। व्यायामशाला के समुचित संचालन के संबंध में एक उपक्रम आवश्यक है।

> "अच्छे एथलीट तैयार करने के लिए व्यायामशालाएं आवश्यक हैं। अब सरकार ने व्यायामशालाओं के लिए सब्सिडी 14 लाख रुपये तक बढ़ा दी है। उम्मीदवारों को व्यायामशालाओं की मंजूरी के लिए जिला खेल अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में एक प्रस्ताव जमा करना होगा।"
> **-भास्कर घाटाले, जिला खेल अधिकारी**

जिम कितना है? : पिछले दो वर्षों में जिले में 83 व्यायामशालाएं स्वीकृत की गई हैं। 2023-24 में 36 और 2024-25 में 47 व्यायामशालाएँ स्वीकृत की गईं। वर्ष 2024-25 में स्वीकृत व्यायामशालाओं में सामग्री स्थापना का कार्य शुरू नहीं हो सका है। पहले जिम के लिए सरकार की ओर से 7 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा रही थी। व्यायामशाला के निर्माण की लागत और सामग्री की बढ़ी हुई लागत के कारण, व्यायामशाला के लिए सब्सिडी बढ़ा दी गई थी।

Result Guarantee Above 90% or Money Back
If U R Not Joining Home Tuitions Then U R Missing Many Things
Mumbai's No.1 Premium Home Tuitions Academy
MUMBAI HOME & PRIVATE TUITIONS
1st to 10th ICSE / CBSE / IB / IGCSE / NIOS / State Boards
XI & XII Sci / Comm. IIT, NEET, MHT-CET
Engg, Degree, Diploma, B.Com, Bsc., BMS, MBA, Gmat, Cat, CET, English Speaking
Rajendra Deshmukh MANAGING DIRECTOR
Any Class Home Tuitions Across Mumbai
Get Admission in MBBS
NEET Qualified / Unqualified Fees 25 Lacs (Inc. Food Acc.)
ADMISSIONS OPEN
Branches : Andheri - Worli - Jogeshwari - Malad - Badar - Borivali - Virar Thane - Vashi - Nerul - Kharghar - Ambernath - Badlapur
Home Tuitions Benefits
Contact : 902 902 9222 / 80 80 80 34 12 / 8446642380 / 9209128153
https://www.mumbaihometutors.com

PRIME KEYS PROPERTIES
Beyond Dreams
BUY | SELL | RENT
FLATS · SHOPS · BUNGALOWS
LANDS · REDEVELOPMENT
Trusted Property Consultant
Residential & Commercial Deals
Best Market Price Assistance
Contact:
+91 9167378057
Your Dream Property, Our Priority

DR. ZUBER SHAH HOSPITAL & POLYCLINIC
Ambernath (W), Maharashtra
Nursing Home Reg. No.: THN-C274*
FACILITIES AVAILABLE
24x7 Emergency Care - Immediate Critical Support
Diabetology & Advanced Diabetic Care
Fever Treatment (Dengue, Chikungunya, Malaria, Influenza)
Cardiology Checkup & ECG Facility
General Medicine Consultation
Vaccination & Immunization Services
Minor Surgical Procedures
OPD & IPD Care Available
Complete Health Checkups
24 HOURS EMERGENCY SERVICE AVAILABLE
DR. ZUBER S. SHAH
M.B.B.S (Reg. No. 2024020955)
Cert. in Diabetology & Emergency Medicine
+91 9323594085 / 8237304085 | Buvapada, K B Road, Ward No. 2/2, Ambernath West, Thane.
Woolen Chawl OPD : 8:00 pm to 11:30 pm | OPD Amber Care : 8149477110

बार-बार होने वाला सिरदर्द हो सकता है खतरे की घंटी

■ डॉ. आशीष मिश्रा
श्रीराम पॉलिक्लिनिक व आयुर्वेदिक दवाखाना

सिरदर्द को आमतौर पर लोग एक साधारण समस्या मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। थकान, नींद की कमी, काम का तनाव, पानी की कमी, या लंबे समय तक मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन देखने के बाद होने वाला सिरदर्द आम बात है और आराम करने से अक्सर ठीक भी हो जाता है, लेकिन हर सिरदर्द सामान्य नहीं होता। जब यह दर्द बार-बार होने लगे या इसके साथ शरीर में कुछ असामान्य बदलाव दिखने लगें, तो इसे हल्के में लेना सही नहीं होता। कई बार यही बदलाव किसी गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या, जैसे ब्रेन ट्यूमर का शुरूआती संकेत हो सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि इसका पहला और सबसे बड़ा लक्षण तेज और असहनीय सिरदर्द होता है, लेकिन मेडिकल रिसर्च बताती है कि शुरूआती चरण में यह बीमारी अक्सर

बहुत साधारण संकेतों के साथ शुरू होती है, जिन्हें लोग सामान्य थकान या तनाव समझ लेते हैं। इसी वजह से कई मामलों में सही समय पर पहचान नहीं हो पाती. ब्रेन ट्यूमर के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि ट्यूमर दिमाग के किस हिस्से में है, उसका आकार कितना है और वह कितनी तेजी से बढ़ रहा है।

ब्रेन ट्यूमर के लक्षण

■ जब दिमाग में किसी जगह असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि शुरू होती है, तो वह आसपास के ऊतकों पर दबाव डालने लगती है। इसी दबाव की वजह से अलग-अलग तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगर ट्यूमर सोचने-समझने या याददाश्त वाले हिस्से में है, तो व्यक्ति को चीजें भूलने की समस्या, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई या निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है। कई लोग इसे बढ़ती उम्र या मानसिक तनाव मान लेते हैं, जबकि यह एक शुरूआती संकेत हो सकता है। इसी तरह अगर ट्यूमर दिमाग के उस हिस्से को प्रभावित करता है जो देखने की क्षमता को नियंत्रित करता है, तो व्यक्ति को धुंधला दिखना, दोहरी छवि दिखाई देना या नजर कमजोर होने जैसी समस्या हो सकती है। कुछ मामलों में मरीज को बोलने में कठिनाई होने लगती है या सही शब्द चुनने में परेशानी महसूस होती ह। ये बदलाव धीरे-धीरे आते हैं, इसलिए लोग इन्हें गंभीरता से नहीं लेते।

'यह परिशिष्ट किसी एक मत या संप्रदाय का प्रचार नहीं, बल्कि मानवता, नैतिकता, आध्यात्मिकता और सहअस्तित्व के सार्वभौमिक मूल्यों का मंच है।'

'आध्यात्मिक संवाद'

आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि का महत्व

हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। साल में चार नवरात्रि आती हैं, जिनमें दो प्रकट और दो गुप्त नवरात्रि होती हैं। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि साधना, शक्ति उपासना और आत्मिक उन्नति के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। वर्ष 2026 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरूआत 15 जुलाई, बुधवार से होगी और समापन 23 जुलाई, गुरुवार को होगा। इन नौ दिनों में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और अच्छे कर्मों के साथ की गई उपासना व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद मां दुर्गा की विधि-विधान से पूजा करें। पूजा स्थल को स्वच्छ रखें और मां को लाल चुनरी, लाल फूल, सिंदूर और श्रृंगार का सामान अर्पित करें. लाल रंग को देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दौरान लाल पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है।

गुप्त नवरात्रि में होती है दस महाविद्याओं की पूजा

मां काली : दस महाविद्याओं में प्रथम स्वरूप। कलियुग में इनकी उपासना शीघ्र फलदायी मानी जाती है।

मां तारा : मोक्ष प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। आर्थिक उन्नति, बाधा निवारण, वाणी दोष दूर करने और शत्रुओं पर विजय के लिए इनकी साधना की जाती है।

मां त्रिपुर सुंदरी (षोडशी) : इन्हें ललिता और राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। इनकी उपासना से सौभाग्य, वैभव, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होने की मान्यता है। श्री यंत्र की पूजा भी इन्हीं से जुड़ी मानी जाती है।

मां भुवनेश्वरी : आदिशक्ति का स्वरूप मानी जाती हैं। सुख, समृद्धि, वाणी की सिद्धि और जीवन में स्थिरता प्रदान करने वाली देवी मानी गई हैं।

मां छिन्नमस्ता : इनका स्वरूप अत्यंत रहस्यमय माना जाता है। मान्यता है कि इनकी साधना से ज्ञान, साहस और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है।

मां त्रिपुर भैरवी: शत्रु बाधा, तांत्रिक कष्टों के निवारण और आत्मबल बढ़ाने के लिए इनकी साधना विशेष मानी जाती है।

मां धूमावती : विपत्ति, रोग, संकट और शत्रु बाधा से रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं।

मां बगलामुखी : शत्रु स्तंभन, मुकदमों में सफलता और विरोधियों पर विजय के लिए इनकी साधना का विशेष महत्व बताया गया है।

मां मातंगी : सुखी गृहस्थ जीवन, प्रभावशाली वाणी, कला, ज्ञान और आकर्षण प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं।

मां कमला : महालक्ष्मी का स्वरूप मानी जाने वाली मां कमला की पूजा से धन, समृद्धि, सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने की मान्यता है।

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 की प्रमुख तिथियां

15 जुलाई	(बुधवार)	प्रतिपदा, घटस्थापना और नवरात्रि आरंभ
16 जुलाई	(गुरुवार)	द्वितीया
17 जुलाई	(शुक्रवार)	तृतीया
18 जुलाई	(शनिवार)	चतुर्थी
19 जुलाई	(रविवार)	पंचमी
20 जुलाई	(सोमवार)	षष्ठी
21 जुलाई	(मंगलवार)	सप्तमी
22 जुलाई	(बुधवार)	अष्टमी
23 जुलाई	(गुरुवार)	नवमी, कन्या पूजन और व्रत समापन

नवरात्रि का समापन (नवमी): 23 जुलाई, 2026 को व्रत के पारण के साथ होगा।

प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचते ही देशभक्ति के रंग में रंगा मेलबर्न

'मां तुझे सलाम' और 'वंदे मातरम' की धुनों से भव्य स्वागत

मेलबर्नः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान मेलबर्न में भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी को देखकर लोग उत्साहति नजर आए और पूरे कार्यक्रम में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी का मेलबर्न में भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी भरा स्वागत किया। इंतजार कर रहे लोगों ने जैसे ही उन्हें देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान लोगों ने 'भारत माता की जय' और 'मोदी-मोदी' के नारे लगाए। कार्यक्रम में उपस्थित कलाकारों ने 'मां तुझे सलाम' और 'वंदे मातरम' की धुनों से प्रधानमंत्री का स्वागत कयिा। इस दौरान महिला कलाकारों ने शवि भक्ति गीत से जुड़ी नृत्य प्रस्तुति प्रस्तुत की। इस मौके पर पीएम मोदी लगातार ताली बजाते हुए कलाकारों का हौसला बढ़ाते रहे।

पेज-1 का शेष

इंडोनेशिया खरीदेगा भारत की ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें...

विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों का यह समझौता भारत की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को नई गति देगा। साथ ही, वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की बढ़ती साख और रक्षा निर्यात क्षमता को भी मजबूती मिलेगी। इंडोनेशिया के साथ यह साझेदारी भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया में एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार के रूप में और मजबूत बनाएगी।

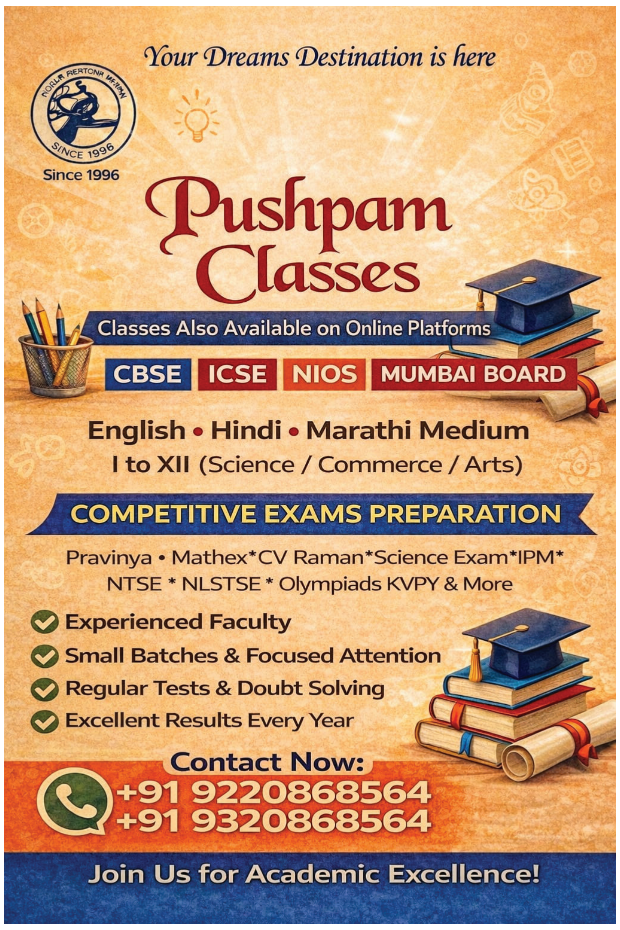

भूकम्पो न, अपितु दुर्बलं निर्माणमेव घातकम् :

वेनेजुएला-देशात् नीतिपाठः

वेनेजुएला-देशे समुपस्थितेन अद्यतन-भूकम्पेन एतत् स्पष्टं जातम् यत् प्राकृतिक-आपदाभिः जनधनहानिः केवलं भूकम्पस्य तीव्रतायाः उपरि न निर्भरति, अपितु भवननिर्माणस्य गुणवत्तायाः, नियामक-व्यवस्थायाः तथा नगर-योजनायाः उपरि अपि अवलम्बते। कैरेबियन-दक्षिण-अमेरिकी-विवर्तनिक-

पट्टिकयोः सीम्नि स्थितत्वात् अयं प्रदेशः स्वभावतः भूकम्प-संवेदनशीलः अस्ति। विशेषज्ञानां मते दुर्बल-निर्माण-मानदण्डाः, जोखिमयुक्तेषु प्रदेशेषु अनियोजित-विकासः तथा भवन-निर्माण-नियमस्य अपर्याप्त-अनुपालनम् इत्येते कारणाः विनाशस्य परिमाणं वर्धितवन्तः।

एषा घटना सीमित-संसाधनयुक्तानाम् अर्थव्यवस्थानां पुरतः महत्त्वपूर्णं नीतिप्रश्नम् उपस्थितयति शीघ्रं न्यूनव्ययेन आवासनिमार्णं प्राधान्येन करणीयम्, उत भूकम्प प्रतिरोधि सुरक्षित-स्थायि-निर्माणम्? नेपाल, इण्डोनेशिया, फिलिपीन्स तथा तुर्किये इत्यादि देशानाम् अनुभवः अपि दर्शयति यत् भूकम्पस्य कारणं भूवैज्ञानिक-पारिस्थितायाः भवन्ति, किन्तु तस्य विनाशकारी-परिणामाः मानवनिर्मित-दोषैः अधिकाः भवन्ति। अतः दीर्घकालिकं समाधानं सुरक्षित-निमार्णे, वैज्ञानिक-नगर-योजनायां तथा भवन-निर्माण-नियमस्य प्रभावी-अनुपालने एव निहितम् अस्ति।

इण्डिगो-विमानसेवायाः नूतना 'इण्डिगो लाइट्' योजना :

केवल-हस्तसामानयुक्तेभ्यः यात्रिकेभ्यः न्यूनमूल्येन विमानयात्रा

देशस्य प्रमुखा विमानसेवा इण्डिगो न्यूनसामर्ग्या सह यात्रां कुर्वतां यात्रिकाणां कृते 'इण्डिगो लाइट्' नाम्नीं नूतनां भाडा-योजनाम् उद्घोषितवती। अस्यां योजनायां केवलं सप्त-किलोग्राम-परिमितं हस्तसामानं (केबिन्-बैगेज्) वहन्तः यात्रिकाः न्यूनमूल्येन विमानयात्रायाः लाभं प्राप्नुयुः। अस्मिन् भाडे पञ्जीकृत-सामानस्य (चेक-इन-बैगेज्) सुविधा न समाविष्टा अस्ति, यदा तु आसन-चयनम्, भोजन-व्यवस्था तथा अन्याः सेवाः आवश्यकतानुसारम् अतिरिक्त-शुल्केन लभ्यन्ते।

एषा योजना जुलैमासस्य प्रथमदिनात् आरभ्य इण्डिगो-संस्थायाः प्रत्यक्ष-आरक्षण-माध्यमेषु उपलब्धा अस्ति तथा जुलैमासस्य पञ्चदशदिनात् आरभ्यमाणासु यात्रासु प्रवर्तते। एषा केवलं देशीयासु तथा अन्तरराष्ट्रीयासु प्रत्यक्ष-उड्डयन-सेवासु आर्थिक-श्रेण्यां प्रवर्तते, संलग्न-उड्डयन-सेवासु तु न लागू भवति। संस्थायाः मुख्य-रणनीति-अधिकारी आलोकसिंहस्य कथनानुसारम् एषा योजना न्यूनसामर्ग्या सह यात्रां कुर्वतां यात्रिकाणां कृते किफायतपूर्णं विकल्पं प्रदास्यति, परिचालन-दक्षताम् अपि वर्धयिष्यति। पूर्वम् एअरइण्डिया अपि 'बेसिक फेयर्' इति सदृशीं योजनां प्रवर्तितवती।

राज्यस्य नियामकशक्तिः न्यायिकहस्तक्षेपश्चः

तमिलनाडु-राज्यस्य सर्वोच्चन्यायालये याचिका

तमिलनाडु-राज्येन मद्रास-उच्चन्यायालयस्य तस्य आदेशस्य विरुद्धं सर्वोच्चन्यायालये विशेषानुमतियाचिका समर्पिता। तेन आदेशेन राज्ये सर्वत्र गोवत्सवधे व्यापकः निषेधः विधीयते। राज्यस्य तर्कः अस्ति यत् मूलजनहितयाचिका केवलं बकरीद्-उत्सवस्य अवसरे सार्वजनिकस्थलेषु पशुवधनिषेधपर्यन्ता आसीत्, किन्तु उच्चन्यायालयेन तस्याः परिधिं विस्तृत्य राज्यव्यापी निषेधः आरोपितः।

राज्यस्य अभिमतानुसारं तमिलनाडु-पशुसंरक्षण-अधिनियमः, १९५८ तथा प्रचलिताः अन्ये अधिनियमाः पशुवधस्य सम्पूर्णनिषेधं न विधास्यन्ति, अपितु अनुज्ञापत्रयुक्तेषु वधशालासु तस्य नियमनमेव विधीयते। राज्येन एतदपि प्रतिपादितं यत् सार्वजनिकस्थलेषु अवैधपशुवधनिवारणार्थं पर्याप्ताः प्रशासनिकव्यवस्थाः पूर्वमेव प्रवर्तिताः सन्ति।

अयं विवादः केवलं गोवधेन सम्बद्धः नास्ति; अपितु न्यायिकसमीक्षायाः मयार्दा, राज्यस्य नियामकशक्तिः, विधायिकायाः नीतिनिर्धारणाधिकारः तथा शक्तिविभाजनस्य संवैधानिकसिद्धान्तः इत्यादीन् गम्भीरान् प्रश्नान् उद्भावयति। सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्णयः भविष्ये न्यायपालिकायाः राज्यकार्यपालिकायाश्च अधिकारसीमां स्पष्टयितुं अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः भविष्यति।

पुनरपि विवादे राष्ट्रिय-परीक्षा-अभिकरणम् :

यूजीसी-नेट् आङ्गलभाषा-परीक्षायां ६७ प्रश्नानां पुनरावृत्तेः आरोपाः

नवदेहली। नीट्-परीक्षायाः विवादानन्तरं राष्ट्रिय-परीक्षा-अभिकरणम् (एन.टी.ए.) पुनरपि विवादस्य केन्द्रे आगतम्। २०२६ तमस्य वर्षस्य जूनमासे आयोजितायां यूजीसी-नेट्-आङ्गलभाषा-परीक्षायां गम्भीराः आरोपाः समुत्थिताः सन्ति। अभ्यर्थिनः तथा विषयविशेषज्ञाः वदन्ति यत् १५० प्रश्नेषु ६७ प्रश्नाः २०२४ वर्षस्य प्रश्नपत्रात् प्रायः यथावत् पुनरावृत्ताः आसन्, बहुषु स्थलेषु उत्तरविकल्पानामपि क्रमः अपरिवर्तितः आसीत्। अस्य विषयस्य स्वतन्त्र-अन्वेषणस्य आग्रहः कृतः अस्ति तथा औपचारिका याचिका अपि समर्पिता अस्ति।

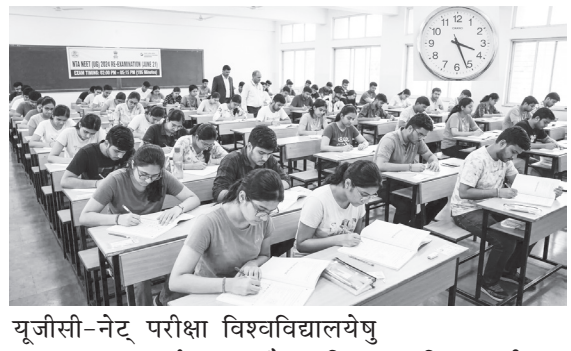

यूजीसी-नेट् परीक्षा विश्वविद्यालयेषु सहायक-आचार्य-पात्रतायै, कनिष्ठ-अनुसन्धान-अनुदानाय (JRF) तथा पीएचडी-प्रवेशाय अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा मन्यते। अतः प्रश्नानां पुनरावृत्तेः आरोपैः परीक्षायाः निष्पक्षता, गुणवत्तायाः मानकाः तथा विश्वासार्हता विषये व्यापकः विमर्शः समुत्पन्नः। शिक्षाविदां मते प्रश्नपत्र-निमार्णे मौलिकता, गुणवत्तानियन्त्रणम् तथा पारदर्शिता सुनिश्चितीकरणम् राष्ट्रिय-परीक्षा-अभिकरणस्य प्रमुखं दायित्वम् अस्ति। तथापि, एतेषाम् आरोपाणां विषये एन.टी.ए.-संस्थायाः आधिकारिकं प्रतिवचनम् अद्यापि न प्रकाशितम्।

Dr. Vandana Mishra
M. A. NET (JRF) PHD

सूक्ष्माचाराः, महद् प्रभावः

पात्राणिः आरवः, सिया, वृद्धः, अध्यापिका, सहकर्मी, परिचालकः, अधिकारी, सूत्रधारः, जनाः

दृश्यम् १ — लिफ्टे
(जनाः तिष्ठन्ति। आरवः उच्चस्वरेण भाषते)
आरवः : ह्यः उत्सवे महान् आनन्दः अभवत्!
सियाः क्षम्यताम्। भवतः वचनं सर्वे शृण्वन्ति।
वृद्धः : वत्स! संकुचिते स्थाने मितभाषिता एव शिष्टाचारः।
आरवः : क्षन्तव्यम्। मया न चिन्तितम्।
सूत्रधारः : सार्वजनिके स्थाने उच्चस्वरः असुविधायै भवति।

दृश्यम् २ — कार्यालये
(सहकर्मी पटलं पश्यति)
सहकर्मी : अयं नवः परियोजनाक्रमः किम्?
अन्यः : अनुमतिं विना पटलनिरीक्षणं न उचितम्। इदं गोपनीयम्।
सहकर्मी : क्षम्यताम्। प्रमादः अभवत्।
सूत्रधारः : परगोपनीयतायाः सम्मानः सभ्यतायाः मूलम्।

दृश्यम् ३ — भोजनालये
(सिया रिक्ते आसने वस्तु स्थापयति)
महिलाः क्षम्यताम्। इदम् आसनं मम।
सियाः रिक्तम् इति मत्वा स्थापितवती।
महिलाः अनुमतिं विना परस्थानोपयोगः न युक्तः।
सूत्रधारः : सार्वजनिकस्थाने अनुशासनम् एव सम्मानः।

दृश्यम् ४ — जनयाने
(आरवः विना कर्णयन्त्रं गीतं शृणोति)
जनाः : भोः! शब्दं न्यूनं कुरुत।
परिचालकः : वत्स! मनोरञ्जनं भवतः अधिकारः, परं शान्तिः सर्वेषाम्।
आरवः : अस्तु। कर्णयन्त्रं धारयामि।
सूत्रधारः : स्वसुखं परक्लेशस्य कारणं मा भवतु।

दृश्यम् ५ — मन्त्रणायाम्
(सिया मध्ये एव वदति)
अध्यापिकाः प्रथमं सर्वेषां वचनं शृणु। मध्ये भाषणम् अशिष्टम्।
सियाः आम्। दोषः मम।
सूत्रधारः : श्रवणं विना संवादः न सिद्ध्यति।

दृश्यम् ६ — शुल्ककक्षे
(आरवः पङ्क्तिं भिनत्ति)
जनाः : पङ्क्तिं मा भिन्द्धि।
अधिकारीः सर्वेषाम् समयः मूल्यवान्। क्रमः एवं सभ्यता।
आरवः : क्षम्यताम्। पङ्क्तौ तिष्ठामि।
सूत्रधारः : क्रमपालनं समाजस्य प्रथमं लक्षणम्। सर्वेः याः आदतयः सूक्ष्माः इव दृश्यन्ते, ताः एव परेषां क्लेशस्य कारणं भवन्ति।
अतः वयं शिष्टाचारम् आचरामः, परस्परं सम्मानयामः, उत्तरदायित्वेन आचरामः।
सर्वे उच्चैः : 'शिष्टाचारः एव संस्कृतेः भूषणम्।'

(यवनिका)

संघर्षेषु लैङ्गिकहिंसा

संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सूच्यां इस्राएल-रूसयोः समावेशः

संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य महासचिवेन २०२५-वर्षसम्बद्धे नवीनतमे प्रतिवेदने प्रथमवारम् इस्राएलस्य तथा रूसस्य सशस्त्र-सुरक्षाबलयोः तेषु पक्षेषु समावेशः कृतः, येषां विषये संघर्षसम्बद्ध-लैङ्गिकहिंसायाः विश्वसनीयाः प्रवृत्तयः अभिलेखिताः सन्ति।

प्रतिवेदनानुसारं २०२५ वर्षे ९,७८८ संघर्षसम्बद्ध-लैङ्गिकहिंसाप्रकरणानां सत्यापनं कृतम्, यत् गतवर्षस्य अपेक्षया उल्लेखनीयां वृद्धिं सूचयति। प्रतिवेदने एकविंशति संघर्षप्रभावितेषु देशेषु बलात्कारः, सामूहिकबलात्कारः, लैङ्गिकदासत्वम्, बलात-विवाहः, मानव-तस्करी, अपहरणम् इत्यादयः गम्भीराः अपराधाः प्रलेखिताः। महिलाः, बालिकाः, पुरुषाः, बालकाः तथा LGBTQI+ समुदायस्य सदस्याः अपि पीडितेषु अन्तर्भवन्ति। परिशिष्टे ७७ उत्तरदायिनः पक्षाः निर्दिष्टाः, तेषु ६२ अराजकीय-सशस्त्रसमूहाः सन्ति। एषा सूची स्वयमेव दण्डस्य आधारः न भवति, किन्तु अन्तरराष्ट्रीयस्तरे मानवाधिकारसंरक्षणम्, उत्तरदायित्वनिर्धारणम् तथा संघर्षकालीनाचारस्य विषये गम्भीरं विमर्शम् उद्भावयति। प्रतिवेदनस्य निष्कर्षान् इस्राएलः तथा रूसः पक्षपातपूर्णान् इति निराकृतवन्तौ। संघर्षेषु लैङ्गिकहिंसाया निवारणाय उत्तरदायित्वस्य सुनिश्चितीकरणमेव न्यायस्य प्रथमः सोपानः।

Uniform educational strategy implemented in UP from new session

Nipun Sankalp Workshop will be organized in all 75 districts

Lucknow: A special campaign is starting across the state from Monday to improve the quality of education in government primary schools of Uttar Pradesh and to effectively implement the Nipun Bharat Mission up to class five. Under this, Nipun Sankalp workshops will be organized in 75 districts. Along with this, the third phase of five-day residential training of district level master trainers will also start at the State Institute of Health and Family Welfare located in Indiranagar. The objective of both the programs is to prepare a common strategy for the new academic session and strengthen the capacity of teachers. Nipun Sankalp workshops will be held in all the districts of the state on different dates from July 6 to 31. On the first day, the joint workshop of Lucknow and Unnao will be held at Hotel Regent located in Nirala Nagar. DIET Principals, Basic Education Officers (BSA), Block Education Officers (BEO), DIET Mentors, SRGs, DCS and ARPs will participate in these workshops. In the workshops, special emphasis will be on effective implementation of educational calendar, extension of Nipun Bharat Mission to class five, inclusion of English and environmental studies in new learning goals, better operation of Bal Vatika, 10 major methods of effective classroom teaching, catch-up teaching, reading culture, independent writing, collaborative supervision, effective use of TLM, parent-teacher meetings (PTM), community participation and strengthening teacher cluster meetings. Hands-on practice of Nipun Bharat Monitoring Center and other digital platforms will also be conducted. On the other hand, in the third phase of Teacher Capacity Building Program, 72 master trainers from 18 districts will take training. In the first two phases, out of 148 nominated master trainers from 37 districts, 135 have been trained, while the training of all the nominated trainers from 29 districts has been completed. In this phase, special training will be given on new NCERT textbooks, print-rich material, use of TLM, classroom based activities and language and mathematics of classes 1 to 3 and subject wise teaching of classes 4-5.

Big decision of Revanth government

Will get free breakfast and lunch till 12th

Hyderabad: Telangana Chief Minister A Revanth Reddy made a big announcement. He informed that the state government has started the scheme of free breakfast and lunch for students from nursery to class 12th. The Chief Minister said this after inaugurating a new plant of Balamritham Scheme. He said that this step is a major effort towards creating a developed and healthy Telangana. The Chief Minister said that parents of poor children have to go to work early in the morning. Because of this, mothers do not have enough time to prepare breakfast for their children in the morning. This scheme has been started to overcome this problem. He said that the state government spends about Rs 27,000 annually on education. The government is taking all necessary steps to improve the infrastructure and standard of education in government schools at par with private corporate schools. The Chief Minister said that the aim of the government is to provide good education to the students. The government considers expenditure on education as an investment. These schemes are being started not for vote bank, but for the better future of the students. Talking about women empowerment, he said that the government wants to promote women of Self Help Groups (SHGs). The government aims to make one crore women millionaires by the year 2034.

More than one lakh schools in the country are still running on the basis of one teacher, the figures are worrying

New Delhi: Even though major steps have been taken to improve school education after the arrival of the new National Education Policy (NEP), the situation is that still more than one lakh schools in the country are running with only one teacher. Who are teaching all subjects to children from class 1st to class 5th in schools.

At the same time, there are still more than five thousand schools in the country in which not a single child is enrolled. This is the situation when the report claims an increase in the number of teachers in schools. According to the report, while the number of teachers in schools in the country was 1.01 crore in 2024-25, it has increased to 1.02 crore in 2025-26. This has come to light regarding the status of school education in the country through the report of Unified District Information System for Education Plus (UDISE Plus) for 2025-26. In the report, the increase in the number of teachers has been presented as the biggest achievement. It has been told that in 2024-25, the total number of teachers in the country was 1,01,22,420, while in 2025-26 it has increased to 1,02,73,020. However, in the same report it has been said that currently there are 100843 schools in the country which are running on the basis of only one teacher. However, in the year 2024-25 the number of such schools was 104125. It is a different matter that the enrollment rate of girls in schools has improved. This number was 48.3 percent in 2024-25, whereas now it has increased to 48.4 percent. At the same time, the number of women teachers in schools has increased, which has now reached 54.9 percent of the total teachers. Earlier it was 54.2 percent.

58 engineering colleges closed across the country

UP and Maharashtra on top

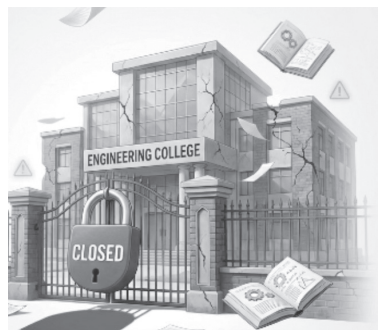

New Delhi: According to the All India Council for Technical Education (AICTE), more than 55 engineering colleges across the country were closed due to various reasons during the 2025-26 academic year, although existing students will be allowed to complete their degrees. A senior AICTE official said, "A total of 58 engineering and technical colleges have been gradually closed (progressive closure) during 2025-26. Progressive closure means that in the academic year for which this approval has been given, the institute cannot give admission to students for the first year. However, the studies of existing students will continue."

In which states were most colleges closed?

- *Among these 58 institutions, maximum number of colleges were closed in Uttar Pradesh and Maharashtra (12 each), followed by Madhya Pradesh (8), Telangana (4) and Punjab (4).*
- *This year, three colleges each were closed in Andhra Pradesh and Rajasthan, while two colleges each were closed in Gujarat, Karnataka, Pune and Tamil Nadu.*
- *One college each in Haryana, Odisha, Uttarakhand and West Bengal was closed.*
- *Of these 58 institutions, three were government aided, while the rest were privately run.*

For what reasons does AICTE close the institute?

The official further said, "During this period, more than 950 courses running in technical and engineering colleges across the country were also closed."AICTE distinguishes between 'progressive closure' and 'complete closure'. In progressive closure, institutions are closed gradually and enrolled students are allowed to complete their studies, whereas in case of complete closure, courses are closed completely and the affected students are transferred to other institutions. AICTE orders closure of institutions for various reasons, including low student intake, inability to retain required faculty, non-compliance with infrastructure and operational norms, etc.

Historic agreement signed between Narmada Award beneficiary states Maharashtra, Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh in the presence of Amit Shah

Jaipur: In the presence of Union Home and Cooperation Minister Amit Shah, a historic agreement has been reached on settlement of pending payments between Narmada Award beneficiary states Maharashtra, Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh. The agreement was signed by Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav in New Delhi today in the presence of Union Home and Cooperation Minister Amit Shah and Union Jal Shakti Minister CR Patil. Senior officials of the Center and the four states were also present in the meeting. This agreement is a historic milestone towards ending the long standing disputes related to cost sharing issues of construction of Sardar Sarovar Project by the States of Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan and Maharashtra, whereby the payments to be made as final settlement of pending dues have been resolved as a one-time settlement. Home Minister Amit Shah said that there was a dispute going on for a long time between Maharashtra, Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh regarding the pending payment of Narmada Award, which has been amicably resolved today. Amit Shah said that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, several historic initiatives have been taken to strengthen water security and promote cooperative federalism in the water sector. He said that the benefit of formation of double engine government in many states under the leadership of Prime Minister Modi ji is that our ability to understand each other has increased, political issues have reduced and many disputes in the country are now being resolved rapidly. The Union Home Minister appreciated the constructive cooperation given by the Governments of Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan and Maharashtra in building consensus on this important inter-state project. Shah said that Madhya Pradesh, Gujarat and Rajasthan especially benefited a lot from this project. With the completion of the dam, water and electricity reached everywhere in these states. He said that the benefit to Rajasthan may seem small, but in the lands where Narmada water has reached, both the value of the land and the fortunes of the farmers have changed.

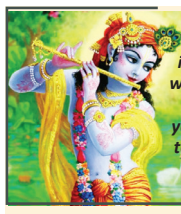

Shri Krishna says... Change is the rule of the world... What was someone else's yesterday is yours today and will be someone else's tomorrow...!!

PUPILS TIMES

"Evil, whether big or small, always causes destruction, because whether a hole in a boat is small or big, it sinks."
Geeta Sermon

Friday, 10 July to 16 July 2026

The first hydrogen train will run from Jind, Haryana on July 17

PM Modi will dedicate to the people

Fare of 'Hydrogen Train'	
Station	Fare (in Rs)
Jind City	Rs. 5
Pandu-Pindara	Rs. 5
Bhambhewa	Rs. 10
Gohana Junction	Rs. 15
Mohana Haryana	Rs. 20
Sonipat Jn.	Rs. 25

Chandigarh: To give impetus to the development of Haryana, Prime Minister Narendra Modi will visit Jind on July 17. During this historic visit, PM Modi will flag off the country's first 'Hydrogen Train' from Jind, which will prove to be a big milestone in the history of Indian Railways. Along with this, the Prime Minister will dedicate to the public the redevelopment work of Jind Railway Station and inaugurate the new medical college built in the city. On this special occasion, a huge public meeting will also be organized in Jind, which will be addressed by the Prime Minister. This country's first hydrogen train is ready.

India is the eighth country with hydrogen train

The coaches of the train have been manufactured at the Integral Coach Factory located in Chennai. Its testing has also been completed successfully. India has become the eighth country to have hydrogen train after Germany, Japan, South Korea, Canada, France and Sweden. The train has been designed in such a way that passengers can get a new experience of convenience, safety and better travel. The train-set consists of two driving power cars (DPCs). Of these, 8 passenger coaches have been installed with each capacity of 1200 kilowatts and total power of 2400 kilowatts.

Maintenance and initial operation

This train is allowed to operate only between Jind and Sonipat section. Its maintenance will be done in Shakurbasti, Delhi. As per safety protocols, the train will be taken to Shakurbasti by a diesel locomotive for maintenance. For the initial three months, the train will be accompanied by trained technical staff. These employees will solve the technical problems coming on the way.

Driven at a speed of 110-120 kilometers per hour

Run through high speed trial of the country's first hydrogen train was conducted on Panipat route. During the trials, the train was run at a speed of 110 to 120 kilometers per hour. The high speed testing of the hydrogen train has now reached its final stage and is being continuously checked on all technical parameters.

Considering service to man as service to Narayan

Government working for the welfare of 25 crore people of the state : CM Yogi

Lucknow: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath did 'Janta Darshan'. During this, he met every complainant from different districts of the state and heard their problems. Giving a heartfelt assurance of providing housing to the needy people and full financial assistance in the treatment of those suffering from serious diseases, he said that our government is working for the welfare of 25 crore people of the state by considering 'Nar Seva as Narayan Seva'. During 'Janata Darshan', Chief Minister Yogi himself reached out to the complainants and listened to their problems one by one. Took their applications and referred them to the concerned administrative and police officers for disposal and directed that the disposal of all the problems should be timely, fair and effective. On this occasion, CM Yogi told the people that the government is determined to provide benefits of welfare schemes to every needy and eligible person and to solve every problem effectively.

The Chief Minister directed the officers to show sensitivity towards public problems. On complaints regarding illegal occupation, the Chief Minister directed the police that if any bully is encroaching on someone's land, then strict action should be taken against him. In matters related to revenue and police, justice should be provided within the time limit and attention should be given to the satisfaction of the victim after resolving the case.

At the same time, the Chief Minister's Office (CMO) shared the photo of 'Janata Darshan' on social media platform

While paying tribute to Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary, CM Yogi wrote in his ex-post, "Today, on the occasion of the birth anniversary of the great son of Mother India and the founding president of Bharatiya Jan Sangh, Revered Dr. Shyama Prasad Mukherjee, he paid tribute by offering flowers at his statue in Lucknow. It is a matter of good fortune for us that the Bengal which Dr. Shyama Prasad Mukherjee ji saved from the 'bloody claws of Pakistan' and kept it an integral part of India, is today witnessing the good governance of the Bharatiya Janata Party which follows his principles and ideals. Salute to his sacred memories.

"Yellow Eyes, A Serious Warning": Never Take Jaundice Lightly

Dr. Arvind singh Rana
MBBS, DNB (General Surgery)
General & Laparoscopic Surgeon Coloproctologist
FACRSI, FAMS FIAGES

Viral hepatitis, commonly known as jaundice, remains a major public health concern in India, particularly during the post-monsoon months from August to October. Although most patients recover completely with timely diagnosis and appropriate treatment, delayed medical care can lead to serious liver complications.

Jaundice is not a disease in itself, but a clinical sign of liver inflammation (hepatitis), most commonly caused by viral infections. Hepatitis A spreads through contaminated food, unsafe drinking water, and poor hygiene, whereas Hepatitis B and C are transmitted through infected blood, unsterilized needles, contaminated medical or dental instruments, and unprotected sexual contact.

Early symptoms often resemble a common viral illness and may include fever, fatigue, loss of appetite, nausea, dark urine, pain in the upper right abdomen, and yellowing of the eyes and skin. Pregnant women, newborns, older adults, and people with weakened immunity are at greater risk of severe complications. Hepatitis B is often called a "silent killer" because it may damage the liver for years before noticeable symptoms appear.

My Advice

Protecting yourself from jaundice begins with simple daily habits. Drink only safe and clean water, avoid stale or unhygienic food, wash your hands thoroughly before meals and after using the restroom, and seek medical attention promptly if symptoms develop. Never rely on self-medication. During recovery, eat light, easily digestible foods, take adequate rest, and strictly avoid alcohol and fried foods.

Remember: Jaundice does not spread through casual contact; it spreads through contaminated food, unsafe water, infected blood, and poor hygiene. Awareness, vaccination where indicated, early diagnosis, and timely medical care are the most effective ways to protect yourself and your family.

PUPILS TIMES
Core Committee
Shivprakash Pandey — Chief Publisher
Vikas Maurya — Co Publisher
Address : Shop No.3, Khatri NX Aprt., Valivali, Badlapur (West) - 421503.
Web : pupilstimes.com

LIC
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
"With you in life, and after life"

POPULAR LIC PLANS:
- Jeevan Labh — Limited Premium, High Returns
- New Children's Money Back — Secure Your Child's Future
- Jeevan Umang — Whole Life Cover + Pension Benefits
- Bima Jyoti — Guaranteed Additions, Safe Growth
- Also Available – Complete Financial Planning Guidance

KEY BENEFITS:
- Life Insurance + Savings Plan
- Child Education and Marriage Planning
- Retirement Planning
- Tax Benefits Available

भारतीय जीवन बीमा निगम
"जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी"
FREE POLICY CONSULTATION

LIC Agent
Archana Shukla
+91 91129 39085
+91 74998 67628
Shop No. 2, Near Vithal Mandir, New Vadavali Chowk, Badlapur (West) – 421503
LIC Agent ID: 04497939

ANURAG SHUKLA CHIEF EDITOR . Mob.: +91 9167378057, E-mail: anurag@pupilstimes.com. www.pupilstimes.com

Printes, Published & Owned by : **ANIL MISRA,** Printed at **SOMANI PRINTING PRESS,** UNIT NO. 04, GROUND FLOOR, N. K. INDUSTRIAL ESTATE, OFF. AAREY ROAD, GOREGAON (E.), MUMBAI, MAHARASHTRA - 400064. **Published at :** 94, 1/3 JAI JAWAN VASAHAT, SHIVSHRUSHTI ROAD, KURLA (EAST), MUMBAI - 400024 (MAHARASHTRA). (The editor does not necessarily agree with the news, artical and advertisements published in this issue. Any disputes are subject to the jurisdiction of the Mumbai court) Editor - **ANIL MISRA** , Mob. : 92208 68564, **Email :** anilmisrapc@gmail.com. **PRGI. No. : MHMUL/25/A2419**